<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

कैबिनेट ने सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नए इक्विटी शेयर जारी करने के लिए आईपीओ के माध्यम से इरेडा को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अधीन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा), मिनी-रत्न सीपीएसई की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से इसमें सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और इरेडा द्वारा नए इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय आईपीओ के जरिए बुक बिल्डिंग आधार पर पब्लिक को प्रत्येक 10 रुपये की इरेडा को 13.90 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देने के लिए जून, 2017 में लिए गए सीसीईए के पहले के निर्णय के बदले में है। मार्च, 2022 में भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालने के बाद पूंजी संरचना में बदलाव के कारण तत्काल निर्णय आवश्यक हो गया है।

यह आईपीओ एक ओर सरकार के निवेश के मूल्य को अनलॉक करने में मदद करेगा और दूसरी ओर जनता को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने और उससे लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह इरेडा को विकास योजनाओं को पूरी करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा जुटाने में मदद करेगा। यह बृहद बाजार अनुशासन और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन में और सुधार करेगा।

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के एक भाग के रूप में की गई प्रतिज्ञा के अनुरूप वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इरेडा को देश में आरई लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

इरेडा द्वारा वित्त पोषित नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संचालन से कुशल और अकुशल जनशक्ति दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इससे कार्बनडाई ऑक्साइड (Co2) उत्सर्जन में कमी आएगी और देश का सतत विकास होगा।

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने इरेडा के आईपीओ को मंजूरी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, एमएनआरई और डीआईपीएएम का आभार व्यक्त किया।

<u>इरेडा के बारे में:</u>

इरेडा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली मिनी-रत्न (श्रेणी-I) सीपीएसई है जिसे वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं के वित्तपोषण करने में लगी हुई है। इसके पास इस क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक की तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। इसे हाल ही में आरबीआई द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिया गया है जोकि इसे आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उच्च जोखिम लेने में सक्षम बनाता है। कंपनी की रेटिंग हाल ही में आईसीआरए द्वारा "एए +" (आउटलुक: पॉजिटिव) से "एएए " (आउटलुक: स्टेबल) में अपग्रेड की गई है।